मं० ग्रोविक एक डी० / 123-85 / 4400 -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० रचना साबुन उद्योग 5-भाई साबुन कालौनी, फरीदाबाद के श्रीमक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसने इसके बाद विखित मामने के अध्वरक्ष में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है ;

श्रीर चूंकि हरियाणा राज्यपान इस विवाद को न्यायिन गैय हेतु निर्दिष्ट करना खांछनीय समझते हैं ;

इसलिये. अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ)द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदा-बाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवत्धकों तथा श्रमिकों के बोच या तो विवादग्रस्त मामले हैं ग्रथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामले हैं न्यायनिर्गग एवं पंचाट छ: मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:---

- (1) क्या संस्था के श्रमिक वर्ष में दो जोड़े यूनिकार्म तथा एक जोड़ा जुता लेने के पान्न बनते हें ? यदि हां, तो किस विवरण सें ?
- (2) वया संस्था के श्रमिक वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 का 20 प्रतिशत के हिसाब से बोनस लेने के हकदार हैं? यदि हां तो किस विवरण से ?

स ० म्रो०िज ०/बिवानो/ 94-85/ 4407 --- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० 1 सिनव एच एस ई.बी., चण्डीगढ़, 2 एकिजिनटन इन्जीनियर म्रोप० डिविजन एच एस ई.बी., नरवाना के श्रमिक श्री जीत सिह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच में इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है;

भ्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए अब आंदौरिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुंथे हिरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा मरकारी घिल्मचना सं 9641—1-श्रम 78-/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी घों असूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को दिवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एं पंचाट तीन मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद- यस्त मामला है या उनत विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री जीत सिंह. पुत्र श्री मादी राम की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रोशिवशिश्रम्बालां/ 150-85/4415.—चूंकि हरियाणा के राज्यशाल की राये है कि मैशा परिवहत श्रीयुक्त, हरियाणा, चणीगढ़ 2. जनरल मैनेजर, हरियाणा राज्य परिवहन, कैयल के श्रमिक श्री हवा मिह तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इस ें इसके बाद लिखित मानले में कोई श्रीद्योगिक विवाद हैं;

ग्रीर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्विष्ट करना वाछनीय समझते हैं :

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारः 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान को गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिन्याणा है राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०-3(44) 84-3-धम, दिनांक 18 अप्रैल 1985 द्वारा उक्त अधिसुचना की आरा 7 के प्रयोग गठित श्रम न्यायालय अम्बाला की विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनण्य एवं पंचाट तीन माम में देने हेम निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से समंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :--

क्या श्री हका सिंह, ॄत्र श्री मोमन राम की सेवाश्रों का समापन व्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रो॰ वि $\phi$ हिसार 98-85 4422—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं॰ 1. मैंनेजिंग डायरैक्टर, हैं फेंड चण्डीगढ़, 2. डिस्ट्रिक्ट मैंनेजर हैं फें:, परसा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया नं. 3, रानिया रोड़, सिरसा के श्रीमक श्री मूप सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद ब्रिबित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करेना बांछनीय समझते हैं;

्स लिए, ग्रव ग्रांखोगिक विवाद ग्रिधिनयम, 1947 का घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तियों का प्रयोग करते दुवें हरियागां के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवस्वर, 1970 के साथ गठित सरकारी ग्रिधिसूचना की धारा 7 के ग्रिधीन गठित श्रम न्यायालय रोह्त को विवादग्रम्न या उससे सुसंग्रत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मात में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रयन्धकों तथा श्रमिक के बीच या ती विवादग्रस्न मामला है या उन्त विवाद से सुसंगत ग्रयवा सम्बन्धित मामला है :---

क्या श्री भूप सिंह, पुत्र श्री जोधा राम की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है।